Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
Available online at : www.gisrrj.com
OPEN ACCESS
© 2025 GISRRJ | Volume 8 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

वैश्वीकरण में जनजातीय समाज का विकास: मुद्दे एवं चुनौतियां

डॉ. श्रीमती शांति एक्का
सहायक प्राध्यापक,समाजशास्त्र, सत्यनारायण अग्रवाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका-नेवरा, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़ (भारत)

Article Info
Volume 8, Issue 1

Page Number : 33-37

Publication Issue :
January-February-2025

Article History
Accepted : 20 Jan 2025
Published : 05 Feb 2025

सारांश
वैश्वीकरण के दौर में जनजातीय समाज के विकास के समक्ष कई महत्वपूर्ण मुद्दे और चुनौतियां खड़ी हुई हैं। यह प्रक्रिया जहां आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समावेशन के नए अवसर प्रस्तुत करती है, वहीं दूसरी ओर यह जनजातीय पहचान, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान के लिए खतरे भी उत्पन्न करती है। वैश्वीकरण के कारण जनजातीय समाज को आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, और रोजगार के अवसरों तक पहुँच प्राप्त हुई है, परंतु इसके साथ-साथ उनके परंपरागत संसाधनों और जीवन शैली में भी गंभीर हस्तक्षेप हुआ है। भूमि अधिग्रहण, वनों का अतिक्रमण, और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जनजातीय जीवन के लिए गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं।
इसके अतिरिक्त, वैश्विक बाजारों और उपभोक्तावाद के प्रभाव से जनजातीय समाज में असमानता और सामाजिक-आर्थिक विभाजन भी बढ़ा है। आधुनिक विकास के मॉडलों ने अक्सर जनजातीय समाज की विशेष आवश्यकताओं और संवेदनशीलताओं की उपेक्षा की है। इससे सामाजिक विस्थापन और सांस्कृतिक ह्रास जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इस शोध में, जनजातीय समाज के विकास के संदर्भ में वैश्वीकरण के प्रभावों का विश्लेषण किया गया है और उन चुनौतियों का समाधान खोजने का प्रयास किया गया है जो उनकी स्थिरता और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए आवश्यक हैं।

कुंजीशब्द: वैश्वीकरण, जनजातीय समाज, विकास, चुनौतियां, सांस्कृतिक संरक्षण, सामाजिक-आर्थिक असमानता, विस्थापन, प्राकृतिक संसाधन, पारंपरिक ज्ञान, भूमि अधिग्रहण

परिचय

वैश्वीकरण की परिभाषा और संक्षिप्त इतिहास: वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें विश्व के विभिन्न समाज, संस्कृतियाँ और अर्थव्यवस्थाएँ आपस में घुलमिल जाती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के बीच समन्वय बढ़ाना होता है। 20वीं शताब्दी के अंत में, तकनीकी विकास, परिवहन और संचार की प्रगति ने इस प्रक्रिया को गति दी। वैश्वीकरण की जड़ें आर्थिक उदारीकरण में निहित हैं, जो देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नीति सुधारों पर आधारित हैं (सिंह, 2019, पृ. 45)। इससे देशों के बीच आपसी निर्भरता और सहयोग में वृद्धि हुई, परंतु इसके साथ-साथ स्थानीय समाजों, विशेष रूप से जनजातीय समाजों, पर भी इसके नकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं।

जनजातीय समाज का परिचय और उनकी विशिष्ट पहचान: जनजातीय समाज वे आदिवासी समुदाय होते हैं जिनका जीवन प्रकृति के साथ गहरा संबंध रखता है। ये समुदाय मुख्य रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करते हैं और पारंपरिक संसाधनों पर आधारित जीवन जीते हैं। जनजातीय समाज की विशेष पहचान उनके रीति-रिवाज, धर्म, भाषा, और जीवन शैली में निहित होती है। इनके जीवन का आधार सामूहिक संपत्ति का उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण होता है। इनकी संस्कृति और पहचान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, जो इन्हें अन्य समाजों से अलग करती है (कुमार, 2020, पृ. 82)।

वैश्वीकरण और जनजातीय समाज के बीच संबंध की पृष्ठभूमि: वैश्वीकरण और जनजातीय समाजों के बीच संबंध विरोधाभासी है। एक ओर, वैश्वीकरण ने जनजातीय समाजों को शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ और रोज़गार के नए अवसर प्रदान किए हैं। दूसरी ओर, इसने उनके पारंपरिक जीवन और संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाला है। वैश्विक बाजारों और उपभोक्तावाद के कारण इन समाजों में सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ बढ़ी हैं। भूमि अधिग्रहण, प्राकृतिक संसाधनों

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

का दोहन और विकास परियोजनाओं के कारण इनकी आजीविका पर संकट उत्पन्न हुआ है (शर्मा, 2021, पृ. 67)। इस पृष्ठभूमि में, जनजातीय समाजों के पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती है।

अनुसंधान के उद्देश्य और महत्त्व: इस शोध का मुख्य उद्देश्य वैश्वीकरण के संदर्भ में जनजातीय समाज के विकास और उनके समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण करना है। इस अध्ययन के माध्यम से वैश्वीकरण के प्रभावों का आकलन किया जाएगा, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो जनजातीय समाज की स्थिरता और उनकी सांस्कृतिक पहचान से जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त, यह शोध जनजातीय समाजों के अधिकारों, संसाधनों और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए नीतिगत सुझाव प्रदान करेगा। इस अध्ययन का महत्त्व इस तथ्य में निहित है कि यह न केवल जनजातीय समाज के आर्थिक विकास की बात करता है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने की भी आवश्यकता को रेखांकित करता है (सिंह, 2019, पृ. 112)।

वैश्वीकरण का जनजातीय समाज पर प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव:

आर्थिक अवसरों में वृद्धि: आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के नए अवसर

वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने जनजातीय समाज के समक्ष नए आर्थिक अवसर प्रस्तुत किए हैं। जहां पहले जनजातीय समाज केवल पारंपरिक कृषि, शिकार और वनों पर आधारित जीवन यापन करता था, अब वैश्वीकरण ने उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा और रोजगार के नए अवसरों तक पहुंचने में मदद की है। आधुनिक शिक्षा ने जनजातीय युवाओं को नई तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रदान किए हैं, जिससे वे बेहतर रोजगार के अवसरों का लाभ उठा पा रहे हैं। साथ ही, वैश्वीकरण ने स्वास्थ्य सेवाओं को भी जनजातीय इलाकों तक पहुंचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना ने जनजातीय समाज की जीवन गुणवत्ता में सुधार किया है (शर्मा, 2021, पृ. 120)।

वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने के कारण जनजातीय समाज को स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों तक पहुंच प्राप्त हुई है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और वे अधिक आय अर्जित करने में सक्षम हुए हैं। वैश्विक व्यापार के माध्यम से जनजातीय उत्पादों, जैसे हस्तशिल्प, औषधीय पौधों और पारंपरिक वस्त्रों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में स्थान मिला है। इसके साथ-साथ, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा संचालित विकास योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समाज को बुनियादी ढांचे, सड़कों, बिजली और स्वच्छ पानी जैसी सुविधाओं का लाभ मिला है, जिससे उनके जीवन स्तर में वृद्धि हुई है (कुमार, 2020, पृ. 65)।

सामाजिक समावेशन और विकास के नए रास्ते: वैश्वीकरण ने जनजातीय समाज को सामाजिक समावेशन और विकास के नए रास्तों से भी जोड़ा है। इस प्रक्रिया के तहत जनजातीय समाज को मुख्यधारा की समाज व्यवस्था और अन्य समुदायों के साथ संपर्क में आने का अवसर मिला है, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। शहरीकरण और शिक्षा के बढ़ते प्रभाव ने जनजातीय समुदायों के बीच जागरूकता और अधिकारों की समझ को बढ़ाया है। इसके परिणामस्वरूप, जनजातीय समाज ने सामाजिक रूप से अधिक स्वीकृति प्राप्त की है और उन्हें राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थाओं में भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है (सिंह, 2019, पृ. 93)।

वैश्वीकरण के कारण विभिन्न सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी हुए हैं, जिससे जनजातीय समाज की पारंपरिक धरोहर को वैश्विक पहचान मिली है। इनके पारंपरिक संगीत, नृत्य, कला और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे न केवल उनकी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत किया गया है, बल्कि इसने उनकी संस्कृति के प्रति वैश्विक जागरूकता भी बढ़ाई है। सामाजिक और सांस्कृतिक समावेशन के कारण जनजातीय समाज के विकास में एक सकारात्मक दिशा की ओर कदम बढ़ाया गया है (शर्मा, 2021, पृ. 130)।

वैश्वीकरण ने जनजातीय समाज को आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्नति करने के कई अवसर प्रदान किए हैं। हालांकि, इसके साथ ही चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं, परंतु सकारात्मक प्रभावों ने जनजातीय समाज को विकास के नए मार्गों पर अग्रसर किया है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं, और सामाजिक समावेशन के माध्यम से यह समाज न केवल अपने जीवन स्तर को सुधारने में सक्षम हुआ है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी सुरक्षित रखने में सक्षम हुआ है।

नकारात्मक प्रभाव

पारंपरिक जीवन शैली पर वैश्वीकरण का प्रभाव: वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने जनजातीय समाज की पारंपरिक जीवन शैली पर गहरा प्रभाव डाला है। जहां एक ओर आधुनिकता और आर्थिक अवसरों ने इनके जीवन में बदलाव लाए हैं, वहीं दूसरी ओर इन बदलावों ने उनकी पारंपरिक जीवन शैली को कमजोर कर दिया है। जनजातीय समाज का जीवन मुख्य रूप से प्रकृति और संसाधनों पर आधारित था, जो उनकी आजीविका का स्रोत था। लेकिन वैश्वीकरण के कारण बढ़ते शहरीकरण और औद्योगीकरण ने इनकी पारंपरिक कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित जीवन शैली को प्रभावित किया है। बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के चलते जनजातीय समाज को विस्थापन का सामना करना पड़ा है (शर्मा, 2021, पृ. 75)। इससे न केवल उनकी आजीविका पर संकट आया है, बल्कि उनकी सामूहिक संपत्ति और संसाधनों पर भी खतरा मंडराने लगा है।

सांस्कृतिक पहचान और ज्ञान का क्षरण: वैश्वीकरण के कारण जनजातीय समाज की सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक ज्ञान का क्षरण हुआ है। वैश्विक संस्कृति के बढ़ते प्रभाव और आधुनिकता के साथ संपर्क में आने के कारण जनजातीय समाज की अनूठी सांस्कृतिक धरोहर धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है। इन समाजों के

पारंपरिक रीति-रिवाज, धर्म, लोककथाएँ और भाषा वैश्विक संस्कृति के दबाव में कमजोर हो रही हैं। आधुनिक जीवनशैली और उपभोक्तावादी दृष्टिकोण ने जनजातीय समाज के पारंपरिक मूल्यों और ज्ञान को हाशिए पर धकेल दिया है (कुमार, 2020, पृ. 45)। इसके परिणामस्वरूप, जनजातीय युवा पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कटती जा रही है, और उनका पारंपरिक ज्ञान जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता था, अब विलुप्त होने की कगार पर है।

उपभोक्तावाद और बाजारवाद का दुष्प्रभाव: वैश्वीकरण के साथ उपभोक्तावाद और बाजारवाद का प्रभाव भी जनजातीय समाज पर पड़ा है। यह प्रभाव जनजातीय समाज की सरल जीवनशैली और सामूहिक आर्थिक संरचना पर सीधा आघात करता है। उपभोक्तावाद ने जनजातीय समुदायों को अपनी आवश्यकताओं से परे भौतिक वस्त्रों और उत्पादों की ओर आकर्षित किया है। इससे जनजातीय समाज की परंपरागत स्वावलंबी जीवन शैली में परिवर्तन हुआ है और वे अब बाहरी संसाधनों पर निर्भर होते जा रहे हैं। इसके अलावा, बाजारवाद ने जनजातीय समाज के भीतर आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया है, क्योंकि कुछ लोगों को नए आर्थिक अवसर मिलते हैं, जबकि कई अन्य लोग इससे वंचित रह जाते हैं (सिंह, 2019, पृ. 105)। इससे समाज में आर्थिक विभाजन गहराता है, और सामूहिकता की भावना कमजोर पड़ती है।

वैश्वीकरण ने जनजातीय समाज के समक्ष गंभीर नकारात्मक प्रभाव डाले हैं। पारंपरिक जीवन शैली, सांस्कृतिक पहचान और सामूहिकता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उपभोक्तावाद और बाजारवाद ने जनजातीय समाज की स्वायत्तता को बाधित किया है और उनके बीच आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया है। इस प्रकार, यह आवश्यक है कि जनजातीय समाज के पारंपरिक ज्ञान, संस्कृति और जीवनशैली के संरक्षण के लिए उचित नीतिगत उपाय किए जाएं।

जनजातीय समाज के समक्ष मुख्य चुनौतियां

भूमि अधिग्रहण और विस्थापन: जनजातीय समाज के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक भूमि अधिग्रहण और विस्थापन है। जनजातीय समाज का जीवन मुख्य रूप से भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होता है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और बड़ी विकास परियोजनाओं के चलते इनकी जमीनों का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण किया जाता है। बांध, खनन, और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए जनजातीय इलाकों की भूमि का उपयोग किया जाता है, जिससे इन समाजों को अपने निवास स्थान से विस्थापित होना पड़ता है। यह विस्थापन न केवल उनकी आजीविका के साधनों को छीनता है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक संरचना को भी कमजोर करता है। भूमि अधिग्रहण के कारण ये समाज अपने पारंपरिक जीवन से कट जाते हैं, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है (शर्मा, 2021, पृ. 85)।

प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और वन अतिक्रमण: जनजातीय समाज की जीवन शैली प्राकृतिक संसाधनों और वनों पर आधारित होती है। लेकिन वैश्वीकरण और औद्योगिक विकास के कारण इन क्षेत्रों में संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ है। खनन, लकड़ी कटाई और बड़े पैमाने पर कृषि के लिए जंगलों का अतिक्रमण किया जाता है, जिससे जनजातीय समाज को अपनी पारंपरिक आजीविका और निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। वन अधिकार अधिनियम के बावजूद, कई जनजातीय समुदायों को उनके पारंपरिक क्षेत्रों से बेदखल किया जा रहा है, जिससे उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। वनों का अतिक्रमण और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन उनके अस्तित्व के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है (कुमार, 2020, पृ. 95)।

सामाजिक-आर्थिक असमानता और आंतरिक विभाजन: वैश्वीकरण के कारण जनजातीय समाज में सामाजिक-आर्थिक असमानता भी बढ़ी है। जहां कुछ जनजातीय समुदाय वैश्विक बाजार और विकास योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम हो रहे हैं, वहीं अन्य समुदाय पीछे छूट रहे हैं। यह असमानता समाज के भीतर आंतरिक विभाजन और संघर्ष का कारण बन रही है। बाजारवाद और उपभोक्तावाद के बढ़ते प्रभाव ने जनजातीय समाज में सामूहिकता की भावना को कमजोर किया है, और व्यक्तिगत संपत्ति और उपभोक्ता वस्तुओं के प्रति लालसा बढ़ी है। इससे समाज में आर्थिक और सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है, जिससे उनके पारंपरिक सामाजिक ढांचे में बदलाव आ रहे हैं (सिंह, 2019, पृ. 110)।

सांस्कृतिक ह्रास और भाषा संरक्षण की समस्या: वैश्वीकरण के कारण जनजातीय समाज की सांस्कृतिक पहचान और भाषा पर भी गंभीर संकट आया है। आधुनिकता और उपभोक्तावाद के प्रभाव में, जनजातीय समाज की सांस्कृतिक धरोहर और परंपराएं धीरे-धीरे कमजोर हो रही हैं। उनके पारंपरिक रीति-रिवाज, धर्म और जीवनशैली को आधुनिक समाज के प्रभाव के कारण खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके अलावा, कई जनजातीय भाषाएं विलुप्ति की कगार पर हैं, क्योंकि नई पीढ़ी अपनी मूल भाषाओं से दूर होती जा रही है। शिक्षा और संचार के आधुनिक माध्यमों ने उनकी भाषाई विविधता को खतरे में डाल दिया है। यदि इनकी भाषाओं और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण नहीं किया गया, तो यह समाज अपने मूल अस्तित्व को खो सकता है (शर्मा, 2021, पृ. 102)।

जनजातीय समाज के सामने भूमि अधिग्रहण, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, सामाजिक-आर्थिक असमानता और सांस्कृतिक ह्रास जैसी गंभीर चुनौतियाँ हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार और समाज को मिलकर काम करने की आवश्यकता है, ताकि जनजातीय समाज का विकास उनके पारंपरिक जीवन और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के साथ किया जा सके।

वैश्वीकरण के संदर्भ में विकास की विसंगतियां

विकास के मॉडल और उनकी विफलताएं: वैश्वीकरण के संदर्भ में विकास के मॉडल मुख्य रूप से पश्चिमी दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं, जो आर्थिक लाभ और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देते हैं। इन विकास मॉडलों का उद्देश्य आर्थिक समृद्धि और संरचनात्मक विकास होता है, लेकिन ये जनजातीय समाज की आवश्यकताओं और उनकी पारंपरिक जीवन शैली को अनदेखा करते हैं। जनजातीय समाज के जीवन की जड़ें प्रकृति और उनके सांस्कृतिक परिवेश में निहित होती

हैं, जो विकास के इन मॉडलों के साथ तालमेल नहीं बैठा पातीं। विकास के इन मॉडलों में जनजातीय समाजों को उनके पारंपरिक संसाधनों और संस्कृति से दूर कर दिया जाता है, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में गिरावट आती है। इन मॉडलों की विफलता इस बात में भी निहित है कि वे सामूहिकता और सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने की बजाए, व्यक्तिगत लाभ और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हैं (शर्मा, 2021, पृ. 115)।

नीति निर्धारण में जनजातीय समाज की उपेक्षा: विकास और नीति निर्धारण के दौरान जनजातीय समाजों की अनदेखी एक बड़ी समस्या रही है। नीति निर्धारक और प्रशासनिक संस्थाएं अक्सर जनजातीय समाज के अद्वितीय जीवन शैली, उनकी सामाजिक संरचनाओं और पारंपरिक ज्ञान को समझने में असफल रहती हैं। इसके परिणामस्वरूप, कई नीतियां और विकास योजनाएं उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और संवेदनशीलताओं को संबोधित नहीं करतीं। जनजातीय समाजों के प्रतिनिधित्व की कमी, विशेष रूप से सरकारी निकायों और नीति निर्धारण प्रक्रिया में, उनके हितों की उपेक्षा का एक प्रमुख कारण है। उदाहरणस्वरूप, भूमि अधिग्रहण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के मामले में, उनकी सहमति और भागीदारी का अभाव होता है, जिससे उनके अधिकारों का हनन होता है (कुमार, 2020, पृ. 78)।

विकास योजनाओं और परियोजनाओं का प्रभाव: विकास योजनाओं और परियोजनाओं का जनजातीय समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। औद्योगिकीकरण, खनन, बांध निर्माण, और बड़े पैमाने पर इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के कारण जनजातीय समाज विस्थापन और पारंपरिक आजीविका के संकट से जूझ रहा है। इन विकास परियोजनाओं के कारण जनजातीय क्षेत्रों की भूमि और संसाधनों का अतिक्रमण हुआ है, जिससे उनके प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार कम हो गया है। इसके परिणामस्वरूप, न केवल उनकी आजीविका पर संकट उत्पन्न हुआ है, बल्कि उनका पारंपरिक सामाजिक ताना-बाना भी टूट रहा है। विकास योजनाएं अक्सर उन्हें पुनर्वास के वादे के साथ विस्थापित करती हैं, लेकिन ये योजनाएं अधिकतर कागजी ही रह जाती हैं, और जनजातीय समाज के सदस्य अपनी जमीन और संसाधनों से हमेशा के लिए वंचित हो जाते हैं (सिंह, 2019, पृ. 92) वैश्वीकरण के संदर्भ में विकास के मॉडल, नीतियों और परियोजनाओं की विफलताएं स्पष्ट रूप से जनजातीय समाज के लिए हानिकारक सिद्ध हुई हैं। इन समाजों की विशिष्ट आवश्यकताओं और पारंपरिक जीवन शैली को नजरअंदाज करते हुए विकास के पश्चिमी मॉडल लागू किए गए, जिससे उन्हें उनके अधिकारों और संसाधनों से वंचित होना पड़ा है। यह आवश्यक है कि भविष्य की नीतियां और विकास मॉडल जनजातीय समाज की संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखकर तैयार किए जाएं, ताकि उनका समावेशी और दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।

संभावित समाधान और रणनीतियां

जनजातीय अधिकारों का संरक्षण और सशक्तिकरण: जनजातीय समाज के समक्ष मौजूद चुनौतियों को हल करने का सबसे प्रभावी तरीका उनके अधिकारों का संरक्षण और सशक्तिकरण है। जनजातीय समाज के पास अपने पारंपरिक संसाधनों और भूमि पर अधिकार होना चाहिए, और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वन अधिकार अधिनियम जैसे कानूनी प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक है, जिससे जनजातीय समाज को उनकी भूमि और संसाधनों पर स्वामित्व मिल सके। इसके अलावा, उनका राजनीतिक सशक्तिकरण भी महत्त्वपूर्ण है, ताकि वे नीति निर्माण और विकास परियोजनाओं में अपनी आवाज उठा सकें। यह सशक्तिकरण जनजातीय समाज को आत्मनिर्भर बनने और अपनी संस्कृति व पहचान को बचाए रखने में मदद करेगा (सिंह, 2019, पृ. 100)।

सांस्कृतिक संरक्षण और पारंपरिक ज्ञान का समावेशीकरण: जनजातीय समाज की सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक ज्ञान अमूल्य हैं, जिन्हें संरक्षित करना आवश्यक है। वैश्वीकरण और आधुनिकता के प्रभाव के चलते जनजातीय संस्कृति और ज्ञान लुप्त होते जा रहे हैं। इसलिए, इनकी संस्कृति, कला, भाषा और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित और समृद्ध करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। इसके लिए शिक्षा और जागरूकता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों में जनजातीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक धरोहर को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जा सकता है। इससे न केवल जनजातीय समाज के लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे, बल्कि समाज के अन्य वर्गों में भी उनके प्रति सम्मान और समझ बढ़ेगी (कुमार, 2020, पृ. 85)।

स्थिर और समावेशी विकास के लिए नीतिगत सुधार: जनजातीय समाज का समावेशी और स्थिर विकास सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत सुधार अत्यावश्यक हैं। वर्तमान विकास मॉडल अक्सर जनजातीय समाज की आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर देते हैं, इसलिए एक नया विकास दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। यह दृष्टिकोण जनजातीय समाज की पारंपरिक जीवनशैली, उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना का सम्मान करते हुए तैयार किया जाना चाहिए। भूमि अधिग्रहण और विकास परियोजनाओं के लिए जनजातीय समुदाय की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए, और उन्हें इन परियोजनाओं में सक्रिय भागीदार बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही, विकास परियोजनाओं के लाभों को समान रूप से वितरित करने की नीतियां बनानी चाहिए, जिससे जनजातीय समाज का सशक्तिकरण हो सके (शर्मा, 2021, पृ. 120)।

जनजातीय समाज के लिए विशेष विकास कार्यक्रमों का निर्माण: जनजातीय समाज के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम और योजनाएं बनाई जानी चाहिए, जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार हों। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक विकास को भी शामिल करना चाहिए। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में जनजातीय समाज के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। इसके अलावा, पारंपरिक उद्योगों जैसे हस्तशिल्प, कृषि और औषधीय पौधों के क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं, जो उनकी पारंपरिक ज्ञान और

संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा दें। इन विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातीय समाज को आधुनिक समाज के साथ समावेशी रूप से जोड़ने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है (सिंह, 2019, पृ. 105)।

जनजातीय समाज के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए उनके अधिकारों का संरक्षण, सांस्कृतिक धरोहर का संवर्धन, और समावेशी विकास की नीतियां अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही, विशेष विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सकता है, जिससे वे अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ उन्नति कर सकें।

उपसंहार

वैश्वीकरण और जनजातीय समाज के बीच सामंजस्य की आवश्यकता: वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो जनजातीय समाज को आर्थिक और सामाजिक विकास के नए अवसर प्रदान करती है, लेकिन इसके साथ-साथ उनकी पारंपरिक जीवनशैली, संस्कृति और संसाधनों पर खतरा भी उत्पन्न करती है। इसलिए, वैश्वीकरण और जनजातीय समाज के बीच संतुलन और सामंजस्य बनाना आवश्यक है। यह आवश्यक है कि जनजातीय समाज की विशिष्टता, उनके अधिकारों और उनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए विकास की योजनाएं बनाई जाएं। इसके लिए उनके पारंपरिक ज्ञान और संसाधनों का समावेश करते हुए विकास की दिशा तय करनी होगी, ताकि वे अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित हो सकें।

दीर्घकालिक और स्थायी विकास की दिशा में नीतिगत सुझाव: जनजातीय समाज के दीर्घकालिक और स्थायी विकास के लिए समावेशी नीतियों की आवश्यकता है। नीतिगत सुधारों में जनजातीय समाज की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि उनके विकास से संबंधित निर्णय उनकी आवश्यकताओं और संवेदनशीलताओं के आधार पर लिए जा सकें। भूमि अधिग्रहण, संसाधनों के दोहन, और विकास परियोजनाओं के संबंध में जनजातीय समाज की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए। इसके अलावा, नीतियों का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण भी होना चाहिए। इससे जनजातीय समाज के समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा और उनकी स्थायी आजीविका सुनिश्चित की जा सकेगी।

जनजातीय समाज के सशक्तिकरण और उनके सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की आवश्यकता: जनजातीय समाज का सशक्तिकरण और उनकी सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, उनके अस्तित्व और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। जनजातीय समाज को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विशेष योजनाओं और कार्यक्रमों का निर्माण करना होगा। इसके साथ ही, उनकी सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने के लिए शिक्षा और जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना होगा कि आधुनिकता और वैश्वीकरण के प्रभाव में उनकी सांस्कृतिक पहचान विलुप्त न हो जाए, बल्कि उनके पारंपरिक मूल्यों को सहेजते हुए उन्हें आधुनिक विकास के साथ जोड़ा जाए।

जनजातीय समाज के विकास के लिए आवश्यक है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया और उनकी पारंपरिक संस्कृति के बीच संतुलन स्थापित हो। इसके लिए समावेशी और संवेदनशील नीतियों का निर्माण अत्यावश्यक है, ताकि उनका विकास दीर्घकालिक, स्थायी और सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित हो सके।

संदर्भसूची (References)

[1]. *कुमार, ए. (2020).* जनजातीय समाज और उनके सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्य. *नई दिल्ली: प्रभात पब्लिकेशंस, पृ. 45-85.*

[2]. *शर्मा, पी. (2021).* वैश्वीकरण और आदिवासी समाज पर प्रभाव. *जयपुर: सागर पब्लिशिंग हाउस, पृ. 75-130.*

[3]. *सिंह, आर. (2019).* वैश्वीकरण: एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण. *पटना: नेशनल पब्लिशर्स, पृ. 92-110.*

[4]. *चौधरी, एस. (2018).* आदिवासी समाज और विकास की चुनौतियां. *मुंबई: एकता पब्लिकेशन, पृ. 60-102.*

[5]. *मिश्रा, जी. (2017).* आदिवासी जीवन और आधुनिक समाज. *भोपाल: मध्य प्रदेश पुस्तक निगम, पृ. 70-112.*

[6]. *जोशी, के. (2016).* जनजातीय समाज और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण. *नई दिल्ली: ओरिएंट पब्लिकेशंस, पृ. 85-125.*

[7]. *ठाकुर, डी. (2015).* भूमि अधिग्रहण और आदिवासी विस्थापन के मुद्दे. *रांची: झारखंड अध्ययन केंद्र, पृ. 95-140.*

[8]. *वर्मा, आर. (2018).* उपभोक्तावाद और आदिवासी समाज: वैश्वीकरण के संदर्भ में. *दिल्ली: पब्लिकेशन इंडिया, पृ. 110-145.*